THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI PATEL): (a) and (b) No, it is not a fact that Central Schemes viz. (i) National Rural Employment Programme, now known as Jawahar Rozgar Yojana (JRY); (ii) Integrated Rural Development Programme (IRDP); and (iii) District Rural Development Agencies (DRDAs) have not been able to make any progress in the North-Eastern region. Though the pace of implementation of these programmes in the North-Eastern region has been slightly slow due to certain factors like scattered population, vast area and poor village level developmental infrastructure, yet the Central Government has made concerted efforts for proper implementation of these programmes in this region.

Recently, a meeting of the Ministers/Secretaries incharge of Rural Development/Panchayati Raj of North Eastern States was organised by the Central Government at Guwahati to ravamp the implementation process in this region. As a follow up of the recommendation of this meeting, fresh initiatives such as direct release of funds to DRDAs, augmentation of funds for essential infrastructures, authorising DRDAs to draw the amount from the Banks on the strength of State Government's guarantee and distribute to beneficiaries in areas where there are no bank branches, etc. have been taken up. Besides, effective monitoring through Area Officers Scheme and Review Team from National Institute of Rural Development, Guwahati are other measures adopted by the Govt. for proper implementation of Rural Development Programmes in this region.

गुजरात में रोजगार आश्वासन योजना

5009. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कच्छ जिले के कितने गांवों/शहरों को सरकार द्वारा रोजगार आश्वासन योजना (ई.ए.एस.) के अंतर्गत शामिल किया गया है और वर्ष 1993-94 और 1994-95 के लिए प्रत्येक गांव, शहर के लिए योजनावार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) बेरोजगार युवकों को विशेष रूप से महाराष्ट्र और गुजरात के युवकों से राज्यवार कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और अब तक इस योजना से कितने बेरोजगार युवक लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) कच्छ जिले के सात खण्डों अर्थात् भुज, अबदासा, लखेरी, नखतराना, बापर, भचाउ तथा अनवर के ग्रामीण क्षेत्र सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत कवर किए जाते हैं। 35.00 लाख रुपए की प्रारंभिक रिलीज प्रति खण्ड 5.00 लाख रुपए की दर से केन्द्रीय सहायता के रूप में सुनिश्चित रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए 1993-94 के दौरान जिले को रिलीज की गयी। अगली रिलीजें जिले को तब करायी जायेंगी जब पहले से उपलब्ध करायी गई निधियों के 50 प्रतिशत का उपयोग कर लिया जाता है। 1994-95 के लिए आवंटन पहले से मुहैया करायी गई निधियों के उपयोग की प्रगति पर निर्भर करेगा।

(ख) 18 वर्ष से ऊपर तथा 60 वर्ष से कम आयु वाले सभी ग्रामीण गरीब सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत काम पाने के लिए पात्र हैं। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, अब तक 32.1 लाख व्यक्ति सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत काम के लिए पंजीकृत किए गए हैं। इनमें से 92,503 व्यक्ति महाराष्ट्र तथा 108948 व्यक्ति गुजरात के हैं। अभी तक रोजगार के कुल 272.40 लाख श्रमदिन सृजित किए जा चुके हैं। श्रम दिनों की संख्या दर्शाने वाला एक ब्यौरा विवरण में है। (नीचे देखिए)

(ग) वर्ष 1994-95 के लिए सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत 1200 करोड़ रुपये की एक राशि आवंटित की गयी है। अभी राज्यवार आवंटन नहीं किए गए हैं, क्योंकि रिलीजें पहले से मुहैया कराई गई निधियों के उपयोग की प्रगति पर निर्भर करेंगी।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित	कवर किए जिलों की संख्या	कवर किए गए खण्डों की संख्या	पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या	सृजित श्रमदिन (लाख श्रम दिन)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	16	120	645221	62.42
2.	अरूणाचल प्रदेश	11	48	5382	0.48
3.	असम	15	69	62277	31.75
4.	बिहार	13	157	असूचित	12.50
5.	गुजरात	17	97	108948	6.75
6.	हरियाणा	6	44	29393	15.20
7.	हिमाचल प्रदेश	3	7	892	0.05
8.	जम्मू व काश्मीर	4	34	असूचित	2.03
9.	कर्नाटक	14	94	503900	32.12
10.	केरल	7	21	19582	2.60
11.	मध्य प्रदेश	23	223	537000	22.90
12.	महाराष्ट्र	20	114	92503	12.02
13.	मणिपुर	5	22	असूचित	असूचित
14.	मेघालय	5	32	असूचित	0.00
15.	मिजोरम	3	20	असूचित	1.04
16.	नागालैंड	7	28	असूचित	असूचित
17.	उड़ीसा	10	143	664546	25.89
18.	राजस्थान	22	122	असूचित	6.73

1	2	3	4	5	6
19.	सिकिक्म	4	4	असूचित	0.83
20.	तमिलनाडु	12	56	55683	4.98
21.	त्रिपुरा	3	18	284053	16.14
22.	उत्तर प्रदेश	20	145	130716	1.09
23.	पश्चिम बंगाल	13	128	67569	1.84
24.	अण्डमान व निकोबार	1	2	302	4.04
25.	दादर व नगर हवेली	1	1	असूचित	0.00
26.	दमन व दीव	1	1	असूचित	0.00
27.	लक्षद्वीप	1	5	2083	0.00
	कुल :	257	1755	3210050	272.40